

## राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

- |  |   |
|--|---|
| <p>मैसर्स अम्बर मिष्टान्न भण्डार, बीकानेर।</p> <p style="text-align: center;">बनाम</p> <p>वाणिज्यिक कर अधिकारी,<br/>घट-द्वितीय वृत्त-बी, बीकानेर।</p> <p>मैसर्स मूधड़ा जनरल स्टोर, बीकानेर।</p> <p style="text-align: center;">बनाम</p> <p>सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,<br/>घट-पंचम, वृत्त-बी, बीकानेर।</p> <p>मैसर्स सी.लक्ष्मी एन्टरप्राइजेज, गंगाशहर रोड, बीकानेर</p> <p style="text-align: center;">बनाम</p> <p>वाणिज्यिक कर अधिकारी,<br/>घट-द्वितीय वृत्त-बी, बीकानेर।</p> <p>मैसर्स होटल लाल जी, स्टेशन रोड, बीकानेर।</p> <p style="text-align: center;">बनाम</p> <p>वाणिज्यिक कर अधिकारी,<br/>घट-द्वितीय वृत्त-बी, बीकानेर।</p> <p>मैसर्स आर.जी.एसोसिटस, त्यागी वाटिका, बीकानेर।</p> <p style="text-align: center;">बनाम</p> <p>वाणिज्यिक कर अधिकारी,<br/>घट-द्वितीय वृत्त-बी, बीकानेर।</p> <p>मैसर्स आनंद होटल, स्टेशन रोड बीकानेर।</p> <p style="text-align: center;">बनाम</p> <p>वाणिज्यिक कर अधिकारी,<br/>घट-द्वितीय वृत्त-बी, बीकानेर।</p> <p>मैसर्स हुकमचंद, पूनमचंद नोखा, बीकानेर।</p> <p style="text-align: center;">बनाम</p> <p>वाणिज्यिक कर अधिकारी,<br/>घट-द्वितीय वृत्त-बी, बीकानेर।</p> <p>मैसर्स खेमचंद गोपालदास राठी, भीनासर, बीकानेर।</p> <p style="text-align: center;">बनाम</p> <p>सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर,<br/>वृत्त-बी, बीकानेर।</p> <p>मैसर्स लालचंद जुगलकिशोर एण्ड कम्पनी स्टेशन रोड बीकानेर।</p> <p style="text-align: center;">बनाम</p> <p>सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर,<br/>वृत्त-बी, बीकानेर।</p> | <p>1. <u>अपील संख्या 1264 / 2015 / बीकानेर.</u><br/>.....अपीलार्थी.</p> <p>.....प्रत्यर्थी.</p> <p>2. <u>अपील संख्या 1265 / 2015 / बीकानेर.</u><br/>.....अपीलार्थी.</p> <p>.....प्रत्यर्थी.</p> <p>3. <u>अपील संख्या 1267 / 2015 / बीकानेर.</u><br/>.....अपीलार्थी.</p> <p>.....प्रत्यर्थी.</p> <p>4. <u>अपील संख्या 1268 / 2015 / बीकानेर.</u><br/>.....अपीलार्थी.</p> <p>.....प्रत्यर्थी.</p> <p>5. <u>अपील संख्या 1269 / 2015 / बीकानेर.</u><br/>.....अपीलार्थी.</p> <p>.....प्रत्यर्थी.</p> <p>6. <u>अपील संख्या 1272 / 2015 / बीकानेर.</u><br/>.....अपीलार्थी.</p> <p>.....प्रत्यर्थी.</p> <p>7. <u>अपील संख्या 1277 / 2015 / बीकानेर.</u><br/>.....अपीलार्थी.</p> <p>.....प्रत्यर्थी.</p> <p>8. <u>अपील संख्या 1278 / 2015 / बीकानेर.</u><br/>.....अपीलार्थी.</p> <p>.....प्रत्यर्थी.</p> <p>9. <u>अपील संख्या 1280 / 2015 / बीकानेर.</u><br/>.....अपीलार्थी.</p> <p>.....प्रत्यर्थी.</p> |
|--|---|

मैसर्स टहलाराम एण्ड संस, रथखाना, बीकानेर।

बनाम

सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर,  
वृत्त-बी, बीकानेर।

.....प्रत्यर्थी.

मैसर्स विजयलक्ष्मी ऑयल मिल, नोखा, बीकानेर।

बनाम

सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर,  
घट-पंचम, वृत्त-बी, बीकानेर।

.....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री मदनलाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित :

श्री ओ.पी.दोसाया,  
अभिभाषक।

श्री अनिल पोखरणा

उप सजकीय अभिभाषक।

.....व्यवसायी की ओर से,

.....राजस्व की ओर से.

निर्णय दिनांक : 09.04.2018

निर्णय

1. उपर्युक्त अपीलें अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर, बीकानेर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा पारित अपीलीय आदेशों के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी हैं, जिसमें अपीलार्थी व्यवहारी ने वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त-बी, बीकानेर (जिसे आगे "कर निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 23 व 24 के अन्तर्गत पारित आदेशों के जरिये कायम की गयी लेट फीस की मांग राशियों को अपीलीय अधिकारी द्वारा पुष्टि किये जाने को विवादित किया है। जिनका विवरण निम्नानुसार है :-

अपील संख्या	कर निर्धारण वर्ष	अपीलीय अधिकारी की अपील संख्या	अ. अधि. आ. दि.	कर नि. आ. दि.
1264/15	2011-12	436/RVAT/bik/13-14	26.03.2015	03.02.2014
1265/15	2011-12	437/RVAT/bik/13-14	27.03.2015	18.12.2013
1267/15	2011-12	439/RVAT/bik/13-14	27.03.2015	10.12.2013
1268/15	2011-12	440/RVAT/bik/13-14	26.03.2015	10.12.2013
1269/15	2011-12	441/RVAT/bik/13-14	27.03.2015	10.01.2014
1272/15	2011-12	472/RVAT/bik/13-14	27.03.2015	09.12.2013
1277/15	2011-12	482/RVAT/bik/13-14	26.03.2015	26.11.2013
1278/15	2011-12	489/RVAT/bik/13-14	27.03.2015	13.12.2013
1280/15	2011-12	494/RVAT/bik/13-14	27.03.2015	13.12.2013
1281/15	2011-12	502/RVAT/bik/13-14	27.03.2015	12.12.2013
1319/15	2011-12	29/RVAT/bik/14-15	24.04.2015	07.02.2014

2. इन प्रकरणों के तथ्य एवं विवादित बिन्दु समान होने के कारण इनको एक ही आदेश से निर्णित किया जा रहा है, निर्णय की एक-एक प्रति प्रत्येक पन्नावली पर पृथक-पृथक रखी जा रही है।

3. प्रकरणों के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी फर्मों का उक्त अवधि का कर निर्धारण आदेश उक्त वर्णित तालिकानुसार पारित किया जाकर मांग राशि कायम की गई। कर निर्धारण अधिकारी ने वार्षिक रिटर्न वेट-10ए प्रस्तुत करने की पावती (Acknowaedgement) या हार्ड कापी देरी प्रस्तुत किये जाने के कारण नियम 19ए में लेट फीस आरोपित कर दी जो अनुचित है। अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा आरवेट एक्ट की धारा 21 का हवाला देते हुए निवेदन किया कि फाइलिंग ऑफ रिटर्न मूल रूप से इलेक्ट्रोनिकली पेश करने को ही रिटर्न प्रस्तुती माना गया है एवं अधिनियम के नियम 19 एवं 19ए में भी विभाग की ऑफिशियल वेबसाईड पर इलेक्ट्रोनिकली रिटर्न पेश करने को ही रिटर्न प्रस्तुत किया जाना माना गया है। प्रस्तुत प्रकरणों में नियम 19(2) का हवाला दिया जाना आवश्यक है कि विभाग की ऑफिशियल वेबसाईट पर इलेक्ट्रोनिकली रिटर्न प्रस्तुत करने के पश्चात् पावती विभाग में रिटर्न पेश करने की अंतिम तिथि के 15 दिवस के अंदर प्रस्तुत करनी आवश्यक है। जबकि नियम 19ए में यह निर्धारित किया गया है कि जहां पर व्यवहारी रिटर्न लेट पेश करता है वहां नियत 19ए के तहत लेट फीस आरोपित करने का प्रावधान है। नियत 19ए में कहीं भी रिटर्न समय पूर्व प्रस्तुत करने के पश्चात् पावती (Acknowledgement) पेश करने का जिक्र नहीं है। अतः निवेदन है कि रिटर्न समय पूर्व प्रस्तुत करने के पश्चात् पावती लेट पेश करने पर नियत 19ए के तहत आरोपित लेट फीस को अविधिक होने से अपास्त करने का निवेदन किया।

अधिकृत प्रतिनिधि ने तर्क दिया कि कर निर्धारण अधिकारी ने बिलंब शुल्क आरोपित करने से पूर्व किसी प्रकार का विशिष्ट नोटिस एवं सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं कर आरवेट एक्ट, 2003 के नियम 48 का स्पष्ट उल्लंघन है। इस संबंध में माननीय राजस्थान कर बोर्ड के निर्णय सहायक आयुक्त, कोटा बनाम मैसर्स इण्डिया ट्यूब मिल्स एण्ड मैटल इण्ड. का उद्धरण प्रस्तुत किया। जिसमें धारा 61 एवं 68 के तहत शास्ति आरोपित करने से पूर्व विशिष्ट नोटिस एवं सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किये जाने को अनुचित मानते हुए विभाग की अपील को खारिज किया गया है। अपीलार्थी द्वारा सभी तिमाही रिटर्न एवं वार्षिक रिटर्न वेट-10ए समय पूर्व विभाग में ऑनलाईन रूप से प्रस्तुत कर दिये गये थे, लेकिन व्यवहारी द्वारा भूलवश वार्षिक रिटर्न 10ए की पावती विभाग में प्रस्तुत करने में देरी हो गई। इस संबंध में निवेदन है कि नियम 19 में रिटर्न ऑनलाईन प्रस्तुत करने के पश्चात् पावती रिटर्न प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि से 15 दिवस के अंदर विभाग में प्रस्तुत करनी आवश्यक है, यदि उक्त पावती 15 दिवस के अंदर प्रस्तुत नहीं की जाती है तो रिटर्न को प्रस्तुत नहीं किया जाना समझा जाएगा। इस संबंध में निवेदन है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा रिटर्नों को बेस मानते हुए एवं रिटर्न के

आधार पर रिटर्न प्रस्तुत मानते हुये कर निर्धारण आदेश पारित किया गया है चूंकि रिटर्न के प्रस्तुत करने का आधार मानकर कर निर्धारण किया जाना इस बात का प्रमाण है कि सभी रिटर्न को वैधानिक माना गया है। अतः सभी रिटर्न को वैधानिकता प्रदान किये जाने के पश्चात् रिटर्न की पावती/हार्ड कापी प्रस्तुत नहीं करने पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा विलंब शुल्क का आरोपण किया जाना नियमों के विरुद्ध एवं विपरीत है।

4. अधिकृत प्रतिनिधि ने तर्क दिया कि राज्य सरकार द्वारा दिनांक 14.07.2014 को नियत 19ए लागू करके विभाग की वेबसाइट पर कन्सेन्ट (Consent) फार्म अपलोड करने के पश्चात् किसी भी वैट रिटर्न की पावती/हार्ड कॉपी विभाग में प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है जो कि इस बात की पुष्टि है कि वैट रिटर्न की पावती/हार्ड कापी नहीं प्रस्तुत करने पर शस्ति/विलंब शुल्क आरोपित नहीं की जा सकती। इस प्रकार विचाराधीन प्रकरणों में अपीलार्थी के विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि ने बताया कि यदि इन प्रकरणों में हमारी रिटर्न Non Filing Of Return की श्रेणी में मानी जाती है तो माननीय कर बोर्ड के वृहदपीठ के निर्णय दिनांक 07.03.2018 के अनुसार उस पर कोई लेट फीस देय नहीं होती है, परन्तु रेकार्ड से स्पष्ट है कि इन समस्त प्रकरणों में व्यवहारीगण ने या तो रिटर्न देरी से प्रस्तुत की है तथा रिटर्न प्रस्तुत करने के प्रमाण स्वरूप Acknowledgement की प्रति नियत अवधि में संबंधित कर निर्धारण अधिकारी को प्रस्तुत नहीं की है। अतः अधिकृत प्रतिनिधि के अनुसार इसे Non-filing of return नहीं माना जा सकता है। अधिकृत प्रतिनिधि ने तर्क दिया कि ऑनलाईन रिटर्न प्रस्तुत ही मूल रूप से रिटर्न प्रस्तुत करने की अभिशंषा को जाहिर करता है। अपीलार्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान निम्न न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये :-

(i) Sibia Healthcare Pvt. Ltd. Vs DCIT (2015) 171 TTJ 145 (Amritsar)

(ii) Smt. G. Indhirani Vs DCIT-TDS (2015) 7 SE' 137 (Chennai)

(iii) CST Vs Sadanand Arya (1979) 43 STC 396

5. उभयपक्षीय बहस पर मनन किया गया। विवरण प्रस्तुत करने के संदर्भ में विधिक धारा 21, नियम 19 व नियम 19ए में निम्न प्रकार है :-

**Sec. 21. FILING OF RETURN -** (1) Every registered dealer shall assess his liability under this Act, and shall furnish return, for such period, in such form and manner, and within such time and with such late fee not exceeding fifty thousand rupees, for delayed furnishing of returns, as may be prescribed, to the assessing authority or to the officer authorized by the Commissioner. (2) Any person or a dealer as may be required by a notice to do so by the Assessing authority or by an officer authorized by the Commissioner in this behalf, shall Purnish return for such period in such from and manner and within such time as may be speci ied. (3) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), where (the Commissioner) is of the opinion that it is expedient in the public interest SO to do may by a

लगातार.....4

notification in the Official Gazette extend the date of submission of the returns of may dispense with the requirement of filing any or all the returns by a dealer or class of dealers.

राज्य सरकार ने नियम 19 में दिनांक 09.03.2011 को संशोधन कर निम्न प्रावधान किये गये

:- 19(1) Returns - (1) The return referred to in sub-section (1) of section 21 of the Act shall be submitted by a dealer in Form VAT 10, VAT 10A and VAT 11 as the case may be,

(2) Every dealer shall submit return electronically through the official web site of the department, unless otherwise notified by the Commissioner. The return shall be digitally signed by the dealer or his business manager and in case it is not digitally signed, the dealer shall furnish, the acknowledgement generated through Official website of the Department and shall be verified by himself or his business manager by affixing his signature on it, within fifteen days of the last date for filing of such return(s), failure to do so shall be deemed to be a case of non filing of returns(s)"

(3) Where the amount of tax, interest or late fee, if not paid electronically, the dealer shall furnish the copy of challan in Form VAT-37, receipt in Form VAT-38 or certificate of tax deduction at source, as a proof of deposit, to the assessing authority or the assessing authority or the officer authorized by the Commissioner, within fifteen days of the last date for filing of such returns (s),

(4) Return in Form VAT-1 shall be submitted, within ninety days of the end of the relevant year, by the following class of dealers: (a) who has opted for payment of tax under sub-section (2) of section 3; or (b) who exclusively deals in goods; (i) which are exempted under the Act; or (ii) on which option to pay tax in lump sum has been exercised under section 5, or (iii) which are taxable at first point in the series of sales and the goods have suffered tax at the said -first point; or (iv) which are taxable at maximum retail price under sub-section (7) of section 4 and such goods have suffered tax at maximum retail price under the said sub-section; or (v) which are exempted under sub-section (3) of section 8 on the condition of payment of exemption fee; or (vi) as may be notified by the Commissioner.

(5) Return in Form VAT- 10 shall be submitted by all dealers other than those enumerated in sub-rule (4) above, along with statement of purchase in Form VAT-07A and statement of sales in Form VAT-08A,

(a) within sixty days of the end of the quarter by the dealers who have deposited less than Rs. 50,000/- as tax under the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003 including the Central Sales Tax Act, 1956, during the previous year.

(b) within forty five days of the end of the quarter by the dealers other than enumerated in clause (a) above.

Explanation Quarter means the period of three months ending on 30th June, 30th September, 31 December and 31 March and month shall mean calendar month.

(6) Annual Return in Form VAT-10A shall be submitted by all dealers covered under subrule(5) within [ten month] from the end of the relevant year.

(7) Where a dealer has more than one place of business, he shall include in the return, the turnover of the principal place of business as well as the turnover of all other places of business,

(8) Where a dealer discovers any omission or error in [Form VAT - 10 or Form VAT WA or Form VAT-11] furnished by him, he may furnish revised return at any time prior to the due date of filing annual return or audit report or on receipt of the notice under subsection (1) of section 24, whichever is earlier.

(9) Notwithstanding any thing contained in sub-rule (1) to (7) above, the return(s) for the period prior to 01-04-2011 may be submitted in such manner and in such form which was in force for that period [(10) Where a dealer has failed to deposit due tax within the period notified under section 20 or has failed to submit a return within the period prescribed under section 21, in such cases, return(s) shall be submitted along with proof of deposit of due tax, late fee and interest, if any. Where such proof is not submitted, it shall be deemed to be case of non-filing of the return. व्यवहारीगण ने विचाराधीन प्रकरणों में विहित तरीके से विहित समय में विवरणियों प्रस्तुत नहीं की है, जिसके कारण विवरणियों हेतु नियम 19ए(iii) के तहत विलम्ब शुल्क का आरोपण किया गया है, चूंकि विलम्ब शुल्क शास्ति नहीं है बल्कि विवरणियों के विलम्ब से प्रस्तुत करने पर शुल्क का निर्धारण है, जिसके लिये नोटिस दिये जाना अपेक्षित नहीं है। उक्त राशि विलम्ब होने पर अपीलार्थी को स्वयं ही विवरणियों के साथ जमा करवाना चाहिये था। नियम 19 एवं 19ए के संबंधित उपबंध इस प्रकार से थे :—

"The Rule 19 (2) as existed on 01.04.2011, was as under: "(2) Every dealer shall submit return electronically through the official web-site of the department, unless otherwise notified by the Commissioner. The return shall be digitally signed by the dealer or his business manager and in case it is not digitally signed, the dealer shall furnish, the acknowledgement generated through Official Web-Site of the Department and shall be verified by himself or his business manager by affixing his signature on it, '[within fifteen days of the last date of filing of such return(s)], failure to do so shall be deemed to be a case of non filing of returns(s)" For the period 01.04.2011 to 31.03.2012 (as substituted by the amendment dated 09.03.2011 w. e.f 01. 04.2011) "19A Late fee. - Where a dealer furnishes the return after the prescribed time, he shall pay a late fee of (i) rupees one hundred per day for a period of first fifteen days and rupees five hundred per day thereafter, subject to a maximum of rupees fifty thousand or thirty percent of the tax assessed whichever is lower, in case he is required to pay tax for each month or part thereof under section 20 of the Act; and (ii) rupees fifty per day subject to a maximum of rupees five thousand, in all other cases."

इसी प्रकार कर बोर्ड के एकलपीठ के निर्णय दिनांक 18.07.2018 अपील संख्या 2251/2015/बीकानेर के निर्णय की वृहदपीठ के द्वारा पुष्टि की गई है। उपरोक्त विवेचनानुसार राजस्थान कर बोर्ड के निर्णय मैसर्स सुनील बनाम कर निर्धारण अधिकारी अपील संख्या 1063/2015/टोंक में दिये गये निर्णय दिनांक 07.03.2018 के अनुसरण में व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपीलें अस्वीकार की जाती है।

उक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलार्थी व्यवहारीगण की अपीलें अस्वीकार करते हुए अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश की एतद्वारा पुष्टि की जाती है।

निर्णय प्रसारित किया गया।

( मदन लाल मालवीय )  
सदस्य